(ii) Establishment of Food Processing Industrial Estates/Parks.

(iii) Setting up/expansion/modernisation of food processing industries.

(iv) Research and Development on food processing, including development of traditional food products, packaging, and utilisation of by products.

(v) Strengthening backward linkages of the processed food industry with primary agricultural, horticultural, milk, meat, poultry and other similar production systems.

(vi) Human Resource Development.

(vii) Promotion of food processing industry through participation in national and international exhibitions, and assistance for studies/surveys/seminars.

(viii) Networking with State Governments through designated nodal agencies, and strengthening them through assistance.

Besides, the Govemment have been taking various policy measures for promoting domestic/foreign/NRI investment and providing fiscal reliefs in Excise and Customs etc. for the processed food sector.

Modernisation of Food Processing Industries

4058. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) -whether Govemment propose to take steps on the modernisation of food processing industry in the country;

(b) if so, the incentives proposed to be given to different States or the private entrepreneurs for the purpose; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir

(b) and (c) Towards its goal of building up a balanced, rapidly growing and self-reliant processed food industry, the Ministry provides policy support for creating a favourable businesss environment for food processing industries, including fiscal and financial incentives, providing financial assistance through the Ministry's Plan Schemes for industrial investments in the setting up by public, private and joint sector companies involving both the Central and State Governments, cooperatives, NGOs, of processed food plants, specialised technical infrastructure for the processed food industry including the Cold Chain from the farm to rural, semi-urban and urban consumers, analytical quality control, safety and hygiene related laboratories, R&D, and technology development laboratories and projects. Human Resource Development for all sectors of the processed food industry. Total Quality Management (TQM) including ISO-9(XX) and other quality assurance and control measures and Marketing Support.

All these have a bearing on modemisation of processed food industry. Our Schemes are project oriented and not State specific. Difficult areas have been defined by the Ministry to include. Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Sikkim, North-Eastern States, Islands and Integrated Tribal Development Projects (ITDP) areas which are eligible to get enhanced rate of Plan assistance.

त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विधुत उत्पादन

4059. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से विद्युत के उत्पादन के लिए त्रिपुरा और मध्य प्रदेश को वर्ष वार कितनी धनराशी जारी की गई है,

(ख) इस अवधि के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन राज्यों में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु उठे गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) आठवीं पंचवर्षिय योजना के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए त्रिपुरा और मध्य प्रदेश को वर्ष वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-॥ में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों सहित देश में किए गए प्रयासों में केन्द्र सरकार द्वारा इसके विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कि पवन ऊर्जा, लघु पन विजली, बायोमास आधारित विद्युत तथा सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा आधारित विद्युत के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए राजकोषीय, वित्तीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन एंव निजी क्षेत्र भागीदारी को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विद्युत के संप्रेषण, संग्रहण, खरीद-वापसी, तृतीय पक्ष को बिक्री के लिए अनुकूल नीतियों की घोषणा तथा बिक्री कर लाभ एंव इरेडा से उदार शर्तों पर ऋण शामिल है।

विवरण-।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश तथा त्रिपुरा को जारी की गई वर्षवार धनराशि

(लाख रु0 में)

क्र. सं.	वर्ष	मध्य प्रदेश	त्रिपुरा
1.	1992-93	7.1	-
2.	1993-94	250.31	-
3.	1994-95	178.39	-
4.	1995-96	30.19	1.86
5.	1996-97	247.00	-

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश तथा त्रिपुरा में प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	मध्य प्रदेश में 8वीं योजना के दौरान वास्तविक उपलब्धि	त्रिपुरा में 8वीं योजना के दौरान वास्तविक उपलब्धि
1.	पवन विद्युत (मेवा)	9.00	-
2.	वायोमास गैसीफायर (मेवा.)	4.355	-
3.	लघु पन बिजली (मेवा.)	4.45	0.1
4.	सौर विद्युत संयंत्र (किवा.) (गैर ग्रिड सम्बद्ध)	12.44	-

मेवा. मेगावाट

किवा. किलोवाट

Solar Thermal Power Projects

4060. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) finances solar thermal power projects;

(b) whether IREDA has designed any ideal size solar thermal plant;

(c) if so, what would be the capacity of such a plant;

(d) whether any model plant has been made operational;

(e) if so, the details thereof alongwith location and capacity; and

(f) whether such plants are commercially viable?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) No, Sir.